

‘चाहे आप रिटायर हो जाएं या घर बैठ जाएं, हम आपको बख्शेंगे नहीं’

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को सार्वजनिक धमकी दी

-रेणु मिश्र-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1, अगस्त। एक तीखे बयान में, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह भाजपा के लिए वोट चुरा रहा है।

इसे देशद्रोह करार देते हुए, राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई जांच और सामने आए खुलासे एक “परमाणु बम” की तरह फटेंगे और इन धमकों के असर में चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।

इसी के साथ, उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह चेतावनी जारी की कि चुनाव आयोग में ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी भाजपा के लिए वोट चोरी में शामिल पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह देश के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के समान है। उन्होंने कहा, “आप कहीं भी हों, सेवानिवृत्त हों या न हों, हम आपको दूध निकालेंगे।”

■ राहुल ने कहा, आपने मतदाता सूचियों से नाम काटने का अगर काम किया है तो वह देशद्रोह के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता।

■ राहुल ने इस संदर्भ में आगे कहा कि “वोटों की चोरी” को पकड़ने में चुनाव आयोग ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया, अतः हमने हमारे साधनों से गत छः महीने में जाँच की है, वोटों की चोरी के प्रकरण की तथा जो जानकारी हमें मिली है, वह विस्फोटक है, “एटम बम” की तरह, और वह धमका चुनाव आयोग को खत्म कर देगा।

■ राहुल ने कहा कि यह विस्फोटक जानकारी पूरी तरह संजोकर, एक सप्ताह में अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान उजागर करेंगे।

■ चुनाव आयोग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी के आरोप आधारहीन व गैरजिम्मेदाराना हैं। अतः चुनाव आयोग के अधिकारी राहुल गांधी के वक्तव्य को तवज्जो नहीं दें तथा जायज़ व पारदर्शी तरीके से अपना काम करते रहें।

विपक्ष के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी को शुरू में मध्य प्रदेश में संदेह हुआ था, और महाराष्ट्र में यह और पुष्टा

आयोग ने हमारा समर्थन या सहयोग नहीं किया, इसलिए हमने खुद के स्तर पर जाँच की। जो हमें मिला, वह एक परमाणु बम की तरह है; एक बार जब यह फट जाएगा, तो चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।”

गांधी ने कहा कि पार्टी ने गहराई और बारीकी से जाँच की। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को पूरे विस्तृत विवरण तक पहुँचने में लगभग छह महीने लगे, और निष्कर्षों का खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग किस तरह भाजपा के पक्ष में वोटों का हेरफेर कर रहा है।

इस तरह के तीखे हमले के बाद, बचाव की मुद्रा में आए चुनाव आयोग के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को “आधारहीन” और “गैर-जिम्मेदाराना” कहकर खारिज कर दिया। आयोग ने एक बयान में कहा, “दैनिक धमकियों और आधारहीन आरोपों के बावजूद, आयोग सभी चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘एसटी वर्ग की बेटियों को समान अधिकार से वंचित रखना अनुचित’

जयपुर, 1 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी वर्ग की महिला के पैतृक संपत्ति में अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि आजादी के सात दशक बाद भी एसटी समुदाय की बेटियों को समान अधिकारों से वंचित करना अनुचित है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधानों की समीक्षा करे

■ हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से, जरूरत हो तो कानून में संशोधन करने को कहा।

और यदि जरूरत हो तो प्रावधानों में संशोधन करे। अदालत ने आशा जताई है कि केन्द्र सरकार इस मामले में विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमला नेती के मामले में निर्देश के आधार पर उचित निर्णय लेगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने ये आदेश मंत्री देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़े मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश अर्जों को खारिज करते हुए एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे दो साल में लॉबिड वाद का निस्तारण करें।

अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अन्य देशों को अब अमेरिका की महँगाई का भार वहन करना पड़ेगा’

ट्रंप का दावा काफी गलत साबित हुआ
टैरिफ बढ़ाने के बारे में

-अंजन रॉय-
अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वाशिंगटन, 1 अगस्त। अमेरिका में 1 अगस्त का दिन है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नए शुल्क प्रभावी हो रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक नई सच्चाई से हतप्रभ नज़र आ रहा है।

शेयरों में व्यापक गिरावट आई है और नए आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।

अभी जारी किए गए जुलाई के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में केवल 73,000 नई नौकरियाँ जोड़ी गईं, जो अब तक की सबसे कम हैं। नई नौकरियों का सुजन, जो अर्थव्यवस्था की गति का एक प्रमुख पैमाना है, कुछ हद तक धीमा हो रहा था और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं।

अमेरिका आमूलचूल परिवर्तन की नई वास्तविकता के प्रति जाग रहा है। एक मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार का गढ़ रहा अमेरिका अब एक संरक्षणवादी (प्रोटैक्शनिस्ट)

■ अमेरिकावासियों को अब महँगी पड़ने लगीं वो वस्तुएँ, जो वो सदा से आसानी से सस्ते दामों में खरीदने के आदी हो गये थे।

■ उदाहरण के लिए, फ्रांस व जर्मनी की वाइन्स व स्विटज़रलैंड की लम्जरी घड़ियाँ।

■ अमेरिका की इकॉनमी भी “स्लोडाउन” के दौर में फँसती जा रही है। उदाहरण के लिए, जुलाई माह के आंकड़ों के अनुसार, केवल 73,000 नये रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जो कई दशकों में सबसे कम है।

■ भारत में निर्मित सामान लगभग गायब ही हो जाएगा, अमेरिका के मार्केट में। क्योंकि 25 प्रतिशत का टैरिफ व ऊपर से रूस से ऑयल खरीदने के कारण लगी पेनल्टी के कारण भारत का माल अन्य देशों की तुलना में महँगा हो जायेगा।

अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहा है। इसने न केवल अमेरिका के करीबी सहयोगियों को निराश किया है, बल्कि आम अमेरिकियों को भी निराश कर रहा है।

देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी, के विपरीत यह एहसास हो रहा है कि अमेरिका के लोगों को उन कई उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करना होगा, जिनकी उन्हें आदत है। बेशक, इस मार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोमवार, बुधवार व गुरुवार को “इन्टर्न्स एंट्री” वर्जित होगी सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट में यह नई व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आग्रह पर की गई है

-जाल खंभाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानून के इन्टर्न्स को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में प्रवेश से रोक दिया है, जो कि विविध मामलों की सुनवाई के दिन होते हैं।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध के बाद उठाया गया है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया, “सक्षम अधिकारियों ने विविध प्रकार के केसों की सुनवाई के दिनों में, यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कानून के इन्टर्न्स के कोर्टरूम के अंदर प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

■ वरिष्ठ व प्रैक्टिसिंग वकीलों की शिकायत थी कि “इन्टर्न्स” की भारी भीड़ के कारण वकीलों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने में भी दिक्कत हो रही थी।

■ साथ ही इन प्रशिक्षु इन्टर्न्स की उपस्थिति के कारण न्यायालय में सभी सीटों भर जाती थीं तथा इन्टर्न्स आग्रह करने के बाद भी इन सीटों को खाली करने को तैयार नहीं होते थे तथा प्रैक्टिसिंग वकीलों को काफी समय खड़ा रहना पड़ता था।

को स्वीकार कर लिया है।” कानून के इन्टर्न्स को नियमित सुनवाई के दिनों, यानी बुधवार और गुरुवार को कोर्ट परिसर और गलियारों में जाने की अनुमति होगी। बार एसोसिएशन ने पहले भी कोर्ट को एक पत्र लिखकर कानून के इन्टर्न्स

पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था, जिसमें कोर्ट के अंदर भीड़भाड़ का हवाला दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था, “यह देखा गया है कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अरुण चतुर्वेदी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने



अरुण चतुर्वेदी

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने बड़ी

■ आने वाले दिनों में और राजनैतिक नियुक्तियों होने की संभावना है।

राजनीतिक नियुक्ति की है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है।

अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही और राजनैतिक नियुक्तियाँ होने की संभावना है। इसमें प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की संभावना है।

1974 से चला आ रहा, 75 बीघा जमीन की अवाप्ति का मामला अब निपटा

अदालत ने जे.एल.एन. मार्ग पर स्थित उक्त भूमि पर मूल पक्षकार के वंशजों का दावा खारिज किया और कहा कि राज्य सरकार ही भूमि का मालिकाना हक रखती है

■ मूल पक्षकार के वंशजों को 1990 में सिविल जज ने राहत देते हुए आदेश दिये थे कि राज्य सरकार उक्त भूमि अवाप्त किये जाने की एवज में पक्षकारों को प्रति बीघा 40,000 रुपये तथा 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे।

■ अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर उक्त आदेश को रद्द कर दिया और यह भी आदेश दिए हैं कि यदि उक्त भूमि को अवाप्त करने और कब्जा लेने की प्रक्रिया में कोई आड़े आता है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है।

रु. प्रति बीघा पर किराये पर दी थी।

इस मामले के जिरह के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि बृजमोहन के निधन के बाद 1, नवम्बर, 1958 को सरकार ने सार्वजनिक कार्यों के लिए ले लिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में मूल पक्षकार त्रिलोकी नाथ साहनी ने 1960 में राजस्व के विभाग के सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष उक्त भूमि के सवाईचक घोषित किये जाने के खिलाफ आवेदन दायर किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि तहसीलदार ने

त्रिलोकीनाथ को घुसपैठिए नहीं मानते हुए, और माफीदार के पट्टे के साथ एक उक्त जमीन पर किरायेदार घोषित कर दिया, हालाँकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को राज्य सरकार के अपील पर खारिज कर दिया था, और अपीलेट अदालतों ने भी कलेक्टर के आदेश को सही माना।

विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि वर्ष 1979 में हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ ने आदेश पारित करे जिसके तहत सरकार को आदेश दिये गये थे, कि त्रिलोकीनाथ जिस भूमि के कब्जे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निर्णय ली। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रह नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं और वह याचिका में की गई प्रार्थना से भी आगे बढ़कर फैसला दे सकता है। एसओजी की रिपोर्ट मिलने के स्रोत नहीं बताने की राज्य सरकार की आपत्ति पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दस्तावेज कहाँ से मिले, वे सही हैं या नहीं, यह महत्व रखता है। यदि दस्तावेज सही हैं तो हाईकोर्ट को जर्नलित में उन पर संज्ञान लेना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद, अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।

■ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी की।

छात्रसंघ चुनाव-राज्य सरकार 10 दिन में जवाब देगी

जयपुर, 1 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दस दिन का समय दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश

■ हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने समय माँगा।

छात्र जय राव की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अदालत में पेश हुए। उन्होंने मामले में जवाब पेश करने के लिए अदालत से दस दिन का समय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा-बून्दी जल परियोजनाओं की समीक्षा की

कोटा, (निसं)। कोटा-बून्दी संसदीय क्षेत्र में जन स्वास्थ्य एवं जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गति लाई जाए और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

■ दिल्ली में आयोजित बैठक में बिरला ने कार्यों में तेजी और पारदर्शिता के निर्देश दिए

लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। दिल्ली में आयोजित वर्चुअल बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, पीएचआई के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, कोटा कलेक्टर पीयूष सामरिया, बून्दी कलेक्टर अक्षय गोदारा सहित दोनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जबकि लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव गौरव गोयल एवं ओएसडी राजेश गोयल बैठक में उपस्थित रहे।

बिरला ने कहा कि सिंचाई और पेयजल से जुड़ी परियोजनाएं आमजन के जीवन से सीधा संबंध रखती हैं, अतः इन कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही अस्वीकार्य होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां कार्य प्रगति पर है वहां गति बढ़ाई जाए, और जिन योजनाओं की स्वीकृति या निविदा प्रक्रियाएं

सशक्त करना और 'हर खेत तक पानी' पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं को विभागीय स्तर पर शीघ्र स्वीकृत किया जाए ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। गुदा मध्यम सिंचाई परियोजना, बटावदी मुख्य नहर, डाबी टैंक और डीपीआर तथा बजट स्वीकृति प्रक्रियाओं को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।

शहरी और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए बिरला ने रामगंजमंडी, सांगोद, इटावा, कैथून और सुल्तानपुर में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया, साथ ही उनके समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि कोटा उत्तर और दक्षिण में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी निविदाएं दोबारा जारी की गई हैं, जबकि हिण्डोली-नैनवां वृहद पेयजल परियोजना का 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

गडुदा और नवनेरा पेयजल योजनाओं के लिए वन विभाग व वन्यजीव विभाग की स्वीकृति

प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हुई। बिरला ने निर्देश दिए कि पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी अड़चनों को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने जल संसाधन और पेयजल ढांचे को समावेशी क्षेत्रीय विकास की आधारशिला बताते हुए अधिकारियों को समन्वय, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, वन विभाग की स्वीकृति और बजट स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं समयबद्ध पूरी की जाएं ताकि किसी भी योजना में बाधा उत्पन्न न हो। बिरला ने निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक निर्बाध रूप से पहुंचे। अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में जल संकट न उत्पन्न हो और दीर्घकालिक समाधान के दृष्टिकोण से योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणधीन परियोजनाएं तय समय सीमा में पूर्ण हों और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

इसके साथ ही, उन्होंने तालाबों के जीर्णोद्धार और अन्य स्थानीय जल संरचनाओं को भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा।

अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित तीन गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान को जारी रखते हुए सूचना पर जिला झालावाड़ के सुलिया चौकी भवानीमंडी सुनेल रोड पर कार्यवाही करते हुए एक कार को रोककर तलाशी के दौरान कार से अवैध मादक पदार्थ 6.615 किलोग्राम अफीम बरामद की गई एवं तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि कोटा के पंजीकरण नम्बर वाली एक स्विफ्ट डिजायर कार अवैध अफीम तस्करी के लिये सुनेल रोड से निकलने वाली है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानीमंडी सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई।

ओम बिरला आज से कोटा प्रवास पर

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर कोटा आएंगे। प्रवास के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। प्रातः 10 बजे वे मेनाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित रेलवे जनसम्पर्क अधिकारियों की संगोष्ठी में भाग लेंगे। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे वे बपावर कृषि मंडी में आयोजित लाड़ली बहना सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ सम्मिलित होंगे।

एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन की साधारण आमसभा का आयोजन

■ आर.के. जैन अध्यक्ष एवं अशोक ढल सचिव बने

नये सदस्यों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसबीआई कोटा अंचल प्रशासनिक कार्यालय कोटा के उपमहाप्रबंधक कल्याण गजवेल्लि थे। विशिष्ट अतिथि सहायक महाप्रबंधक कोटा नवीन लखवानी एवं मुख्य प्रबंधक सत्येन्द्र जयसवाल थे। एसोसिएशन के चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी एस पी अग्रवाल की देखरेख में हुए। जिसमें आर के जैन को अध्यक्ष पद एवं अशोक कुमार ढल को सचिव

पद, आर एस गुप्ता, एल आर सिन्हा, पवन अग्रवाल एवं संजीव शंकर झा, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य पद पर निर्वाचन निर्वाचित हुए। अन्य सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव भी सर्वसम्मति से संपन्न हुए। आम सभा पश्चात् मनोरंजन से भरपूर गेम्स, हाऊजी व लक्की ड्रा आदि ने सभी को हर्षित एवं रोमांचित किया। अन्त में जयपुर सर्किल के उपाध्यक्ष आर एस गुप्ता द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का आधार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राम गोपाल मराठा, जयदेव चौधवानी, संतोष कर्मचन्दानी, प्रकाश खुशलानी और पी सी सोनी का योगदान रहा।

‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ पर विचार गोष्ठी

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय कोटा के रामानुजन हॉल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) की स्थानीय इकाई राजकीय महाविद्यालय कोटा एवं राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के संयुक्त तत्वावधान में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा प्रो. विजय कुमार पंचोली, विभाग संयोजक नवीन भित्तल भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. रामावतार मेघवाल (विभाग सह-संयोजक) ने किया। कार्यक्रम में प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के मुख्यवक्ता प्रो.भवानी सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि 1986 में लागू शिक्षा नीति में समय के अनुसार बदलाव की

आवश्यकता के कारण नये संदर्भ और परिस्थितियों के अनुकून राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए हमें सकारात्मक दिशा में कार्य करने होगा। समयानुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध पहलुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। क्रियान्वयन की तीव्रता पर उन्होंने कहा कि इसके लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को मिलकर काम करना होगा।

‘अपात्र लाभार्थी से स्वेच्छा से नाम हटवाएं’

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा संचालित गिव-अप अभियान के तहत कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त लाभ को त्यागने की अपील की है, ताकि वे वास्तविक पात्र व जरूरतमंद परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें जो अभी तक इससे वंचित हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि सरकार की मंशा अपात्र लाभार्थियों पर कटोर कार्रवाई करने की नहीं है, बल्कि उन्हें स्वेच्छा से योजना से बाहर होने का अवसर देने की है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन या महंगे व्यावसायिक वाहन (जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख या उससे अधिक हो), बड़े पक्के मकान, एयर कंडीशनर, अत्यधिक बिजली बिल, बड़ी कृषि भूमि अथवा विरासत में प्राप्त संपत्ति है, वे इस खाद्य सुरक्षा योजना के

तहत पात्र नहीं हैं। इसके अलावा जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी सेवा में है या निजी क्षेत्र में एक लाख रुपए से अधिक मासिक वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, वे भी योजना से बाहर होने के योग्य हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशनधारी के राशन कार्ड में जुड़े ऐसे आर्थिक रूप से सक्षम सदस्य जो अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी इस सूची से नाम हटवाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से नाम हटवाने वाले लाभार्थी भविष्य में संभावित प्रशासनिक कार्रवाई जैसे गेहूँ की वसूली आदि से बच सकेंगे। साथ ही, इससे उन सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा जो पात्र होते हुए अभी तक योजना के लाभ से वंचित हैं। जिला कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए।

नाम परिवर्तन

मैं, कोशल, माता सैनिक संख्या 15712726N NK विकास कुमार, निवासी गांव, पोस्ट-फुगाना, तहसील-बुढाना, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-247776, मैंने अपना नाम कौशलया देवी (जन्मतिथि 01.05.1958) से बदलकर कौशल (जन्मतिथि 01.01.1963) रख लिया है। भविष्य में मुझे कौशल, (जन्मतिथि 01.01.1963) के नाम से ही जाना पहचाना जाए। शपथ पत्र संख्या BZ.256354 दिनांक 30.07.2025

मैं, जगमेर पिता सैनिक क्रमांक 15712726N NK विकास कुमार, निवासी ग्राम, पोस्ट-फुगाना, तहसील-बुढाना, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-247776, ने अपना नाम जगमेहर (जन्मतिथि 15.08.1953) से बदलकर जगमेर (जन्मतिथि 01.01.1962) रख लिया है। भविष्य में मुझे जगमेर (जन्मतिथि 01.01.1962) के नाम से ही जाना पहचाना जाए। शपथ पत्र संख्या BZ.256355 दिनांक 30.07.2025

तरुण कुमार जिला संगठन मंत्री बने

कोटा, (निसं)। भारतीय किसान संघ जिला कोटा के संगठन मंत्री के पद पर तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जगेंद्र सिंह ने कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान यह घोषणा की। इस दौरान भारतीय किसान संघ के संस्थापक सदस्य मोहनलाल नागर, राष्ट्रीय घुमंतू कार्य प्रमुख मणिलाल लबाणा, प्रदेश राजस्व मंत्री शिवराज पुरी, चितौड़गढ़ प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा, महिला प्रमुख राममूर्ति मीणा, रजनी धाकड़, संतोष नागर, कोटा संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, संभाग उपाध्यक्ष मोहनलाल नागर, कोटा जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा, बूंदी जिला अध्यक्ष संतोष दुबे, बारां जिला अध्यक्ष अमृतलाल, कोटा जिला मंत्री रूपनारायण यादव, कार्यालय मंत्री महावीर नागर, बूंदी जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री चंद्रप्रकाश मीणा, जिला उपाध्यक्ष भूरालाल धाकड़ समेत हाड़ौती कार्यकर्ता एवं किसान बंधु उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (गैराज)

क्रमांक :- ननिको(उ) / गैरीज / 2025 / 1260-1270दिनांक :- 24.07.2025

--: अल्पकालिन पुनः ई-निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा उत्तर के गैरीज अनुभाग में वृक्षारोपण के लिए गढ़वे करने हेतु टेंडर मय ड्रिलमशीन किराये पर मय डीजल आपूर्ति हेतु संबंधित संवेदकों से ऑनलाईन निविदा पद्धति से नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक निविदा प्रपत्र एवं शर्तें SPPPRajasthan.Gov.In, Kotamc.org, <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्राप्त कर सकेंगे।
U.B.N. Code No. DLB2526WSRC 13049
NIB : DLB2526A4091

उपायुक्त (गैरीज)
नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांक:--ननिको(उ.) / जनस्वा0 / 2025 / 482-492दिनांक :- 29.07.2025

--: निविदा निरस्त सूचना :-

इस कार्यालय द्वारा जारी नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के मुख्य मार्गों व अन्य आयोजनों हेतु आवश्यकतानुसार सफाई कार्य हेतु 310 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य का वार्षिक अनुबंध कार्य हेतु ई-निविदा सूचना क्रमांक ननिको(उ) / जनस्वा0 / 2025 / 372-84 दिनांक 23.06.2025 को निविदा जारी की गई थी। उक्त निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।
यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

अति० आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल मांगरोल जिला-बारां (राज0)

E-mail :- npmangrol05@gmail.comPH. No. :- 07457-223203

क्रमांक / भूमे / 2025 / 2102दिनांक 30.07.2025

सार्वजनिक / आपति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका मांगरोल ने नामान्तरण, मकान बेचान अनापति, हक्याग अनापति, भवन निर्माण स्वीकृती इत्यादि हेतु पत्रावलीयाँ प्राप्त हुई हैं। जिनकी जांच की जा रही है। अतः निम्नांकित आवेदनों के निस्तारण किये जाने में किसी को कोई आपति हो तो सूचना प्रकाशन के अन्दर अवधि 7 योंम में अपना आपति मय दस्तावेज पालिका में उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर सकेंगे। अवधि समाप्ति पश्चात कोई एतराज / आपति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम आवेदक	पता	सम्बन्धित विवरण
1.	अब्दुल सलाम पुत्र पीर मोहम्मद	वार्ड नं. 20 सिपाई मोहल्ला मांगरोल	हक्याग अनापति
2.	जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद	वार्ड नं. 21 जामा मस्जिद के पास, मांगरोल	नामान्तरण
3.	कृष्णमुरारी पुत्र भैरुलाल गालव	वार्ड नं. 04 ईटावा रोड काज्या टोडी मांगरोल	नामान्तरण
4.	गायत्री बाबू पत्नी सत्यनारायण गाडव	वार्ड नं. 18 छोटा बाजार, मांगरोल	मकान बेचान अनापति

राज.संवाद / सी / 25 / 7301अधिशारी अधिकारी

**भारत सरकार**

अन्नदाताओं का सम्मान

समृद्ध राष्ट्र का निर्माण

आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में

प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी

के द्वारा

₹20,500 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर

**02 अगस्त 2025** | **प्रातः 11:00 बजे** | **वाराणसी, उत्तर प्रदेश**

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को मिली

₹3.70 लाख करोड़ की सम्मान राशि

विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक

किसानों को सालाना ₹6000 की सहायता

पीएम किसान के 85% से अधिक लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान

पीएम किसान के 4 लाभार्थियों में कम से कम एक महिला लाभार्थी

बीज से बाजार तक किसानों के साथ हैं पीएम मोदी

**11 वर्षों में कृषि बजट में 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी, ₹22,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.27 लाख करोड़ हुआ**

**बीते 11 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन 246 मिलियन टन से बढ़कर 354 मिलियन टन हुआ एवं गांववानी फसलों का उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 362 मिलियन टन हुआ**

**मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने व उर्वरकों के उचित उपयोग हेतु किसानों को 25 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी**

**पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को ₹1.83 लाख करोड़ का भुगतान**

**बीते 11 सालों में ₹23 लाख करोड़ से अधिक MSP पर गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन फसलों की खरीद**

**पिछले 11 सालों में ₹14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किरफायती दामों पर खाद की आपूर्ति**

**ई-नाम प्लेटफॉर्म से 1522 कृषि मंडियां जुड़ीं; ₹4.20 लाख करोड़ से अधिक सुविधाजनक लेन-देन हुए**

**‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ - माइक्रो इरिगेशन कवरेज 42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर हुआ**

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज या डीडी किसान चैनल पर देखें



फॉलो करें:
 @AgriGol

अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें



CBC 01102130002/2526

आवासन मंत्रालय के सचिव ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का निरीक्षण किया

सचिव श्रीनिवास ने लांगड़ियावास में स्थित प्लांट का दौरा किया

जयपुर। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव कातिकियाला श्रीनिवास ने शुक्रवार को जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के ग्राम लांगड़ियावास में स्थित ठोस अपशिष्ट आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का दौरा किया। यह प्लांट राजस्थान सरकार की स्वच्छ भारत



सचिव कातिकियाला श्रीनिवास (बीच में) ने जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के ग्राम लांगड़ियावास में स्थित ठोस अपशिष्ट आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का दौरा किया।

■ श्रीनिवास ने प्लांट प्रमुख से प्लांट की कार्य प्रणाली, उपयोग लाई जा रही तकनीकों, अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया,पर्यावरणीय लाभों पर विस्तृत जानकारी ली

मिशन (शहरी) के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जिसे ज़िंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (जयपुर) लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में संचालित किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के निदेशक जुझर प्रतीक चंद्रशेखर एवं आयुक्त, नगर निगम जयपुर

(हेरिटेज) डॉ. निधि पटेल ने श्रीनिवास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य शासन विभाग व निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता भी उपस्थित रहे।

श्रीनिवास ने प्लांट प्रमुख से प्लांट की कार्यप्रणाली, उपयोग लाई जा रही नवीनतम तकनीकों, अपशिष्ट से ऊर्जा

निर्माण प्रक्रिया एवं पर्यावरणीय लाभों पर विस्तृत जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण प्लांट का भ्रमण कर इसकी कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

इस अवसर पर श्रीनिवास ने स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम, जयपुर एवं ज़िंदल समूह के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्लांट इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलकर शहरी चुनौतियों का सतत समाधान

प्रस्तुत कर सकते हैं। यह संयंत्र न केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक है बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम योगदान दे रहा है। फरवरी, 2025 से संचालित इस प्लांट में प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे का प्रसंस्करण कर प्रतिदिन 12 मेगावाट-घंटा का विद्युत उत्पादन किया जाता है जिस से लगभग 2.5 करोड़ रूपए की आय नगर निगम को होती है।

जन जागरूकता अभियान में यातायात नियमों की जानकारी दी

जयपुर। राजधानी जयपुर में पुलिस उपायुक्त यातायात सुमित मेहरडा के निदेशन में यातायात पुलिस जयपुर की ओर से यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर हर वर्ग तक यातायात जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस कड़ी में शुक्रवार को यातायात शिक्षा टीम द्वारा केपीएस उड़ान स्कूल विद्याधर नगर एवं टीवीबी गर्ल्स पब्लिक

■ पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार एवं उनकी टीम ने विद्यार्थियों एवं बाल वाहिनी वाहन चालकों को यातायात संकेतकों से अवगत कराया

सीनियर सैकण्डरी स्कूल अम्बाबाड़ी पर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें यातायात शिक्षा टीम के पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार एवं उनकी टीम ने विद्यार्थियों एवं बाल वाहिनी वाहन चालकों को यातायात

संकेतकों से अवगत कराया और यातायात नियमों जैसे वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग करने, तेज गति से वाहन नहीं चलाने, वाहन की निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करने, अनावश्यक हॉर्न का उपयोग नहीं करने,

नशों में वाहन नहीं चलाने आदि के बारे में समझाईश की गई सड़क दुर्घटना के समय अच्छा मददगार बनने तथा मुख्यमंत्री आनुष्मान जीवन रक्षा योजना के बारे में अवगत कराया गया। स्कूलों में ट्रैफिक क्लब बनाकर विद्यार्थियों को ट्रैफिक वालंटियर की तरह भी यातायात का व्यावहारिक प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली की समझ के लिए ट्रैफिक पॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मियों के साथ कुछ समय के लिए नियोजन के लिए प्रेरित किया गया।

डॉक्टर से चालीस लाख रुपये की रंगदारी मांगी

जयपुर। करणी विहार थाना इलाके में एक डॉक्टर से चालीस लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। घर के मेन गेट पर धमकी भरा लेटर एक लिफाफे में रखकर फेंका गया। लेटर में लिखा कि ज्यादा होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। इस संबंध में पीड़ित डॉक्टर ने थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस टीम की ओर से मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि करणी विहार के रहने वाले एक डॉक्टर ने मामला दर्ज करवाया है कि वह चित्रकूट इलाके में प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। गत दो दिन पहले रात में अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश उसके घर के बाहर आए और घर के मेन गेट के ऊपर से एक लिफाफे में धमकी भरा लेटर फेंक कर चले गए। अगले दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल रहे थे। मेन गेट के पास उनको लिफाफा पड़ा दिखाई दिया। लिफाफा खोलकर देखने पर उसमें धमकी भरा लेटर मिला। धमकी भरा लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ था कि ज्यादा

■ अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश उसके घर के बाहर आए और घर के मेन गेट के ऊपर से एक लिफाफे में धमकी भरा लेटर फेंक कर चले गए

■ लेटर में लिखा कि ज्यादा होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा

होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप चालीस लाख रुपए दे देना। लेटर के जरिए धमकी देकर चालीस लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पीड़ित डॉक्टर की ओर से धमकी भरा लेटर मिलने के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस की ओर से मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है। पुलिस टीमों की ओर से पीड़ित डॉक्टर के घर के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है।

अनुसूचित जाति के प्रबुद्धजनों के साथ सामाजिक न्याय मंत्री ने बैठक ली

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री 3अविनाश गहलोल ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के उन्धान के लिए कृत-संकल्पित है। सरकार की मंशा है कि सामाजिक न्याय की सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। गहलोल बुधवार को अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध नागरिकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का उन्धान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यालय अम्बेडकर भवन के सभागार में हुई बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास को संकल्पना दशा और दिशा पर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में छात्रवृत्ति प्रक्रिया में सुधार, आक्षेपों का तुरंत निस्तारण, छात्रवृत्ति के लिए तय आय सीमा को बढ़ाने,

■ ‘अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित’

■ गहलोल बुधवार को अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध नागरिकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की

छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने, छात्रावासों के आधुनिकीकरण, अंबेडकर भवनों में पुस्तकालय खोलने, पंचतीर्थ योजना में खासकर युवाओं को शामिल करने, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था बेहतर करने, छात्रावासों की मॉनिटरिंग करने, नए छात्रावास खोलने सहित अन्य विषय संस्थाओं द्वारा उठाए गए।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि विभाग द्वारा

एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर चल रहे धरने के 100 दिन पूरे

जयपुर । राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहे धरने को लेकर कहा कि आज धरने को 100 दिन पूरे हो गए मगर सरकार अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील नहीं है,उन्होंने कहा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर उन्होंने बड़ी रैली की व लोक सभा में भी मामला उठाया।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से आज 100 दिन आंदोलन के पूरे होने पर धरने पर बैठे युवाओं तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने भारत के तिरंगे के प्रतीक कलर के गुब्बारे लगाकर सरकार को संदेश दिया कि हम संविधान की भावना का सम्मान करते हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं ।

प्रधानमंत्री किसानों को जारी करेंगे पीएम-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी (उत्तरप्रदेश) से देशभर के किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। मोदी 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। इस आयोजन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहेंगे। शर्मा राज्य स्तरीय समारोह में कृषि विभाग की पॉलीकोइस, सीर ऊर्जा पंप संयंत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, तारबंदी और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत लाभार्थी किसानों को अनुदान राशि के प्रतीकात्मक चेक वितरण करेंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पात्र परिवार और लाभार्थियों से संबंधित प्रश्न लगाया था, जिसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण



दिन भर रुक रुक कर छितराई हुई बारिश का दौर चला। अजमेर रोड पर आई तेज बारिश के बाद लगा लंबा जाम।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में बांसवाड़ा में आयोजित होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह

■ किसानों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए पीएम-किसान जैसी योजना एक मील का पथर है : सांसद मदन राठौड़

राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था। योजना के तहत अब तक 19 किश्तों में 3.69 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। पहली किश्त में जहां देशभर के 3 करोड़ 16 लाख 21 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में 6324 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए थे, वहीं 19वीं किश्त के रूप में 10 करोड़ 6 लाख 85 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में 23500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर सैचुरेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। 2023 में जहां भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना में शामिल किया गया था, इसके बाद नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत लगभग 25 लाख और पात्र किसान परिवारों को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद सितंबर 2024 से विशेष अभियान चलाकर फिर से वंचित पात्र परिवारों को योजना में शामिल करने का प्रयास किया गया।

मरीज को जयपुर लेकर आ रही एंबुलेंस ट्रक में घुसी

जयपुर। कानोता थाना इलाके के जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे-21 पर सांप डसने वाले मरीज को जयपुर लेकर जा रही एंबुलेंस ट्रक में घुस गई। इस हादसे में मरीज और उसकी मां

■ हादसे में मरीज और उसकी मां की मौत हो गई, अन्य दो लोग घायल हैं

की मौत हो गई। वहीं अन्य दो लोग घायल हैं। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके के गुर्जर सोमला गांव के दशरथ योगी (21) को गुरुवार देर रात घर में सोते समय सांप ने काट लिया था। मां मुधरी देवी (48) और दो रिश्तेदार मरीज को सीमला से दौसा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद शुक्रवार सुबह दशरथ को जयपुर एसएमएस अस्पताल लिए रेफर किया गया। जहां एंबुलेंस में उनके साथ दो रिश्तेदार और थे। इस हादसे में एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में मरीज दशरथ काफी देर तक तड़पने बाद दम तोड़ दिया ।

युवाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम है युवा संसद : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधान सभा के सदन में तेरह राज्यों के 168 युवा देश की सुरक्षा से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद करेंगे। विधान सभा में शनिवार को प्रातः 10 बजे इस एक दिवसीय युवा संसद का राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष देवनानी शुभारम्भ करेंगे। समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित इस युवा संसद का राजस्थान विधान सभा के यू-ट्यूब चैनल पर सजीव प्रसारण किया जायेगा।

देवनानी ने बताया कि देश के दस राज्यों राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात और तीन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ व नई दिल्ली के 55 विधायनों के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के चयनित 168 युवा छात्र-छात्राएं आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करवाने के प्रयासों पर संवाद कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के हल का मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे।

विधान सभा सदन में 56 युवा

सार-समाचार

अरशद हुसैन बने इवेंट मैनेजर्स डे के ग्लोबल कन्वीनर



वह भी गुलाबी नगर जयपुर से। हुसैन ने जब नेतृत्व संभाला था तब इवेंट मैनेजर्स डे का आयोजन सिर्फ 32 देशों तक सीमित था और अब इसका दायरा बढ़कर करीब 70 देशों तक पहुंच चुका है। इस तरह जयपुर से जुड़े एक प्रोफेशनल का नाम आज वैश्विक मंच पर पूरे सम्मान के साथ लिया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय कमेटी में 11 देशों के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने सर्वसम्मति से अरशद को पुनः कन्वीनर चुना। इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस निर्णय को न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि माना, बल्कि इसे राजस्थान की इवेंट मैनेजमेंट क्षमताओं की वैश्विक पहचान के रूप में देखा जा रहा है। यह इवेंट इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणादायक पल है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने का हौसला देगा।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आज

जयपुर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती की अध्यक्षता में शनिवार को प्रातः 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में प्रदेश स्तरीय “डॉ. कलाम स्टार्टअप यूथ अवॉर्ड 2.0” प्रदेश बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, स्थाई आमंत्रित सदस्य, जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री उपस्थित रहेंगे बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सम्बोधित करेंगे।

राजस्थान को “जैविक खेती राज्य” घोषित करने की मांग



जयपुर। राजस्थान को “जैविक खेती राज्य” घोषित करने की मांग को लेकर एक छात्र द्वारा शुरू किया गया प्रयास अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। वर्ष 2022 में जयपुर के 13 वर्षीय छात्र श्रेष्ठ मंगल ने भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आग्रह किया गया था कि राजस्थान को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक रूप से “जैविक खेती राज्य” का दर्जा दिया जाए। यह पहल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के सहयोग से शुरू की गई थी और शुरूआती चरण में इसे 1,000 छात्रों का समर्थन मिला था। लेकिन पिछले तीन वर्षों में यह मुहिम राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है और आज 2025 तक, इस ज्ञापन को देशभर से 1,05,107 छात्रों का समर्थन मिल चुका है, जो इस अभियान की गहराई और प्रभाव को दर्शाता है। श्रेष्ठ मंगल ने न केवल राजस्थान के लिए जैविक खेती की मांग की, बल्कि यह भी प्रस्ताव रखा कि कृषि को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के अंतर्गत लाकर उसे उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह एक विशेष केंद्रीय बजट और स्पष्ट रोडमैप तैयार करे, जिससे 2030 तक राजस्थान को एक मॉडल जैविक राज्य बनाया जा सके।

निर्देश दिए। दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालय से बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के खुलेंगे द्वार संसदीय कार्य मंत्री ने कहा यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट में प्रदेशवासियों को जो ऐतिहासिक सींगतें दी है उनकी समयबद्ध धरातल पर

क्रियान्विति सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालय खुलने से प्रदेश भर की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खुलेंगे। पटेल ने कहा गत बजट में झंवर में महाविद्यालय की घोषणा हुई थी, गत सत्र में ही महाविद्यालय शुरू

हो गया और भवन निर्माण कार्य 4.5 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। उन्होंने कहा इस बजट में केरु में भी नवीन महाविद्यालय की सीगात मिली है।

बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समयावधि में कार्य पूर्ण करें:-पटेल

ने राजस्थान शहरी पेयजल सिल्वरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (रुडसिस्को) के सहायक अभियंता राजेश व्यास को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा भवन निर्माण कार्य को बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समयावधि पूर्ण करें।

+



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को वर्तमान ट्रैफिक स्थिति को सुगम एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए।

जयपुर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने की योजना बनायें

मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर बैठक में निर्देश दिये

जयपुर, 1 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था को तुरंत सुगम एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात संचालन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत दीर्घकालीन कार्ययोजना के लिए गृह एवं यातायात विभाग, जेडीए, शहरी विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों व आमजन से सुझाव लेकर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था विकसित करें। मानसून के बाद हीरापुरा बस टर्मिनल से बसों का संचालन किया जाए।**

शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस एवं यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को जागरूक करते हुए ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर शहर में वाहनों के सुगम संचालन

और जाम से राहत के लिए व्यापारियों एवं आमजन से सुझाव लेकर व्यवस्तम मार्गों पर वन वे ट्रैफिक संचालन की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के चिन्हित ऑटो और बस स्टैंड के स्थानांतरण को शीघ्र लागू किया जाए। इसी क्रम में हीरापुरा

बस टर्मिनल से मानसून के तुरंत बाद बसों का संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों की सख्त पालना करने और उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर सिग्नल फ्री ट्रैफिक संचालन की कार्ययोजना बनायीं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ट्रंप को जवाब -भारत अमेरिका से एफ-3 5 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा

वाइट हाउस में फरवरी 2025 में ट्रंप ने मोदी से ये विमान खरीदने की पेशकश की थी

नई दिल्ली, 1 अगस्त। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हालांकि, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इस बीच भारत की ओर से भी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका के एफ-35 लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है।

ब्लूमबर्ग ने अधिकारियों के हवाले से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स की खरीद में तेजी लाने पर विचार करने के बावजूद, भारत सरकार द्वारा अमेरिका से एंटीशनल डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने की संभावना नहीं है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका को सूचित कर दिया है कि वह एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने का इच्छुक नहीं है।

■ **रिपोर्ट के अनुसार भारत घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित पार्टनरशिप में ज्यादा रुचि रखता है। भारत की ओर से अब तक ट्रंप की पेशकश का जवाब नहीं दिया गया।**

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2025 में अमेरिका की यात्रा की थी और व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी।

इस दौरान ट्रंप ने भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया है कि भारत सरकार घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित पार्टनरशिप में ज्यादा रुचि रखती है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस बारे में जवाब नहीं दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

एक अगस्त से भारत से आयातित उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने रूस से आयात करने के लिए भारत पर दंडात्मक उपाय के तौर पर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की, यह 25 प्रतिशत शुल्क से अलग होगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उसके शुल्क बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने आगे कहा- “भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है, और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं, जबकि हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करें।”

‘चाहे आप रिटायर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जारी रखने का आग्रह करता है। इन बयानों को नज़अंदाज करना ही सबसे अच्छा है।”

मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे भारत विशेषी बयान दे रहे हैं, जो उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नहीं करना चाहिए।

राहुल गांधी अगले सप्ताह कर्नाटक के अपने दौरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जहाँ उनसे चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के संबंध में कुछ विस्फोटक खुलासे की उम्मीद

है। इस सब का निशाना है बिहार में मतदाता सुचियों का पुनरीक्षण और वो तरीका, जिससे बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों मतदाताओं को सूचियों से हटा दिया गया है।

विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को इसी सत्र में समाप्त कर देना चाहता है, ताकि चुनाव आयोग परिष्कृत बंगाल जैसे अन्य चुनाव वाले राज्यों में भी ऐसा ही न करें। लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल की स्पष्ट और सटीक बात, और नरेन्द्र मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आक्रामकता, मोदी और उनकी टीम के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों की उपस्थिति का विरोध

नई दिल्ली, 1 अगस्त। विपक्ष ने राज्यसभा में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सदन के बीचोंबीच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों को भेजे जाने का आरोप लगाते हुए इसका कड़ा विरोध किया है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समापति हरवर्ष की इंकलाबी संतान है। उसने अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया था। इस दौरान, प्रतिवादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा 2(2) के प्रावधानों के आधार पर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी पेश कर वाद खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि यह अधिनियम एससी वर्ग के सदस्यों पर लागू नहीं

‘एसटी वर्ग की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पैदा करता हो। अनुच्छेद 14 महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अपने पिता की इंकलाबी संतान है। उसने अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया था। इस दौरान, प्रतिवादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा 2(2) के प्रावधानों के आधार पर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी पेश कर वाद खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि यह अधिनियम एससी वर्ग के सदस्यों पर लागू नहीं

छात्रसंघ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मांगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई टाल दी।

याचिका में बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केवल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। वहीं, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत, हर साल छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए। कमेटी की सिफारिश के अनुसार सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव हो चाहिए।

बिहार की पूर्व मतदान सूची में 22 लाख मृत पाये गये

पटना, 01 अगस्त। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में चलाये गये विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार पूर्व में सूची में जुड़े 22 लाख मतदाता मृत पाये गये। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्त में जानकारी दी गयी कि बीएलओ की सहायता से कराये गये सर्वेक्षण में 22 लाख, 69 हजार (2.83 प्रतिशत) मतदाता मृत पाये गये, 36 लाख, 28 हजार (4.59 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम अन्य स्थानों पर भी पंजीकृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस अभियान के तहत राज्य भर में बीएलओ के माध्यम से कुल सात करोड़, 89 लाख, 69 हजार, 844 गणना प्रपत्र मुद्रित करा कर संबंधित मतदाताओं के बीच वितरित किये गए थे। इनमें से 16 लाख से अधिक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किये गये।

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

उन्हें 17000 करोड़ के लोन फ्रॉड व मनी लॉण्डरिंग के मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिये बुलाया

■ **लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है, जब जांच एजेन्सी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।**

नई दिल्ली, 1 अगस्त। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के चेयरमैन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि उन पर देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। ईडी ने उन्हें 17,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड और मनी लॉण्ड्रिंग मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह कार्यवाही मुंबई और अन्य शहरों में एडीएजी की कंपनियों से जुड़े 35 से ज्यादा टिकानों पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद हुई है। ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएएल) के तहत शुरू की गई है। जांच वित्तीय अनियमितताओं और लोन के गलत इस्तेमाल के एक जटिल नेटवर्क पर केन्द्रित है।

17,000 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी

इससे अनिल अंबानी की विदेश यात्राओं पर रोक लग गई है। यह एक साफ संकेत है कि ईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह अनिल अंबानी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और सेबी जैसे अन्य नियामक निकायों की रिपोर्ट पर आधारित है। ईडी की जांच में लोन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से, 2017 और 2019 के बीच यस बैंक की ओर से अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के लोन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने कई अनियमितताओं की बात कही है। इसमें बैंकडेटेड क्रेडिट अप्रुवल, उचित जांच की कमी और विभिन्न ग्रुपों और शेल कंपनियों के फंड का गलत इस्तेमाल शामिल है।

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी व रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार

दिल्ली में 71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा



शाहरुख खान



विक्रांत मैसी



रानी मुखर्जी

फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ‘सैम बहादुर’ की वैभवशा और मेकअप के

की प्रेम कहानी (हिंदी) के लिये कोरियोग्राफर वैभवी मंचेट को मिला।

■ **शाहरुख खान को फिल्म “जवान” तथा मैसी को “12 वीं फेल” के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। रानी मुखर्जी को “मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे” के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है।**

लिए भी सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार रॉकी और रॉनी

पल्लोवरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार; गाँड बल्चर

कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप का दोषी माना

बैंगलुरु की विशेष अदालत में शनिवार को सजा सुनाई जायेगी

■ **प्रज्वल रेवन्ना जनतादल (सैक्यूलर) के नेता हैं तथा हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र तथा कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के पुत्र हैं।**

ली थी तथा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा का ऐलान अब शनिवार (2 अगस्त) को होना है। रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं। जब 2,000 से अधिक अश्लील वीडियो विलप, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुई

थी। रेवन्ना के खिलाफ पहली शिकायत अप्रैल 2024 में एक महिला ने दर्ज कराई थी, जो उनके परिवार के फार्माहाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उसने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार बलात्कार करने और किसी भी घटना के बारे में बताने पर दुर्व्यवहार के वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

‘अन्य देशों को अब अमेरिका की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का असली असर धीरे-धीरे सामने आएगा।

कुछ चीजें, जिनकी कीमतों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि यूरोपीय वाइन, अब पहले से ज्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने यूरोपीय वाइन को छूट वाली सूची में शामिल नहीं किया, जैसा कि फ्रांस, जर्मनी या इटली के बेहतरतीन वाइन उत्पादक चाहते थे।

अमेरिका अपने उत्तरी पड़ोसी, कैनडा को सबसे अधिक सामान्य शुल्कों में से एक से दंडित करना चाहता है। अमेरिका ने कैनडा के निर्यात पर 35 प्रतिशत का शुल्क लगाया, क्योंकि कैनडा, अमेरिका की इच्छानुसार, एक समझौते को अंतिम रूप देने में विफल रहा।

मेक्सिको और चीन को फिलहाल इस मौजूदा दौर में छूट दी गई है, क्योंकि भारत से कर्कड़ों, जूतों और एक्सेसरीज के निर्यात पर भी भारत के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत का शुल्क लागेगा।

शुल्क के वास्तव में प्रभावी होने से पहले एक छोटी सी मोहलत अभी

अधिक शुल्क वाली श्रेणियों में रखा गया है। क्लिक्स चडियाँ पर अमेरिका में प्रवेश के लिए 39 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। एक ब्रिटिश-आधारित कंपनी, जो यूके और यूएसए में क्लिक्स चडियाँ का यह व्यापार संभालती है, का कहना है कि इससे मांग में कमी आएगी।

भारत को अपेक्षाकृत उच्च शुल्क श्रेणी (25 प्रतिशत) में रखा गया है। तथापि, यदि रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए डॉनल्ट ट्रम्प के दंडात्मक शुल्क भी साथ-साथ शुरू होते हैं, तो भारत को अमेरिकी बाजारों से बाहर निकाला जा सकता है।

(भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात, भारत इन वस्तुओं के सबसे बड़े सप्लायरों में एक है) पर अब 10 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। ताइवान, जो दूसरा प्रमुख निर्यातक है, पर थोड़ी कम दर, यानी 20 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

शुल्क के वास्तव में प्रभावी होने से पहले एक छोटी सी मोहलत अभी

उपलब्ध है। अभी और अक्टूबर के बीच की गई सभी वर्तमान शिपमेंट को नए शुल्कों से छूट मिलेगी। हालांकि, यह एक छोटी सी मोहलत है, क्योंकि इन शिपमेंट को बहुत पहले से बुक किया जाता है, इसलिए इतनी कम अवधि में इनमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता।

कई देशों ने अब राहत और संतोष की भावना व्यक्त है कि घोषित शुल्क कम से कम पेशानी वाले हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाएगा, जिसे वह एक जीत मानता है, क्योंकि पहले 41 प्रतिशत की कहीं अधिक दर घोषित की गई थी। शुल्क यह इस देश को इंडोनेशिया, पाकिस्तान या वियतनाम जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के साथ एक सापेक्ष समानता पर रखता है। शुल्क का अंतिम प्रभाव संतुलित होगा। क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है तथा निर्यातक, मांग पर शुल्क के प्रभाव की भरपाई के लिए अपने अंतिम कीमत कम करने का विकल्प चुन सकते हैं।

हालांकि इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं,